

## देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02

अंक - 265

जौनपुर, शनिवार, 22 जून 2024

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य - 2 रुपये

संक्षिप्त खबरें

**अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल शुरू करने से पहले आतिशी राजघाट पहुंची**

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा से प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन पानी छोड़े जाने की अपनी मांग को लेकर अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल करने से पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आतिशी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता, आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह मौजूद थे। आतिशी ने इससे पहले सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हर संभव प्रयास करने के बाद भी हरियाणा सरकार दिल्ली को पुरा पानी नहीं दे रही है, इसलिए वह दक्षिणी दिल्ली के भोगल इलाके में दोपहर 12 बजे से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगी। आम आदमी पार्टी (आप) की नेता ने एक्स पर कहा था, आज से 'पानी सत्याग्रह' शुरू करूंगी... मैं आज 12 बजे से भोगल, जंगपुरा में अनिश्चित कालीन अनशन शुरू करूंगी। जब तक दिल्ली वालों को हरियाणा से अपने हक का पानी नहीं मिलेगा तब तक अनशन पर रहूंगी। हरियाणा पिछले दो सप्ताह से दिल्ली को उसके हिस्से के 613 एमजीडी पानी के मुकाबले प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन कम पानी छोड़ रहा है।

**नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए - मारावती**

लखनऊ, संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने मांग की कि नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार को नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से निर्दोष छात्र पिस रहे हैं। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पेपर लीक की आड़ में सियासत करना ठीक नहीं है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 पांच मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी जिसमें लगभग 24 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इस परीक्षा का परिणाम 14 जून को घोषित किये जाने की उम्मीद थी, लेकिन परिणाम चार जून को ही घोषित दिये गये थे क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले ही पूरा हो गया था। सरकारी और निजी कॉलेजों के एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट-यूजी का आयोजन देशभर में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा कराया जाता है।

## सीएम योगी और राज्यपाल 10वें अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज 10वें अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहां राजभवन में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। राज्यपाल जी एवं मुख्यमंत्री जी ने योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल योग साधकों, प्रशिक्षुओं सहित समस्त प्रदेशवासियों को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर राज्यपाल जी ने कहा कि 10वें अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस-2024 की थीम 'स्वयं और समाज के लिए योग' का उद्देश्य योग को एक वैश्विक आंदोलन के रूप में फैलाना तथा सामाजिक स्वास्थ्य समस्याओं और जनकल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ६

यान केंद्रित करना है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रीनगर में 10वें अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य योगाभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी कि वास्तव में अगर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो केवल योग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं।

राज्यपाल जी ने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस हमें अपनी ऋषि परम्परा की विरासत पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। योग जीरो बजट वाला दुनिया का सबसे पहला हेल्थ इंश्योरेंस है। योग स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है, जो स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। हमारी भारतीय आयुष पद्धति सम्पूर्ण



आरोग्यता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है, जिसकी ओर पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है। सम्पूर्ण आरोग्यता प्रदान करने की दिशा में योग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल जी ने कहा कि राजभवन द्वारा विकसित वेबपोर्टल

में प्रतिदिन योग करने संबंधी शपथ का अभियान 14 जून, 2024 से 18 जून, 2024 तक चला। इसमें प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा अन्य लोगों द्वारा भी नामांकन कर प्रतिभाग किया गया। इस अभियान में कुल 26,22,467 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग कर शपथ

ली गयी और यह एक विश्व रिकार्ड बन गया है। राज्यपाल जी ने कहा कि बढ़ते हुए तापमान का दुष्प्रभाव सभी के जीवन पर पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने का सर्वोत्तम उपाय है पौधे रोपण है। उन्होंने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि अधिक से अधिक

पौधे रोपण करें तथा रोपित पौधों की नियमित देखरेख करें। प्रधानमंत्री जी द्वारा 'एक पौधा मां के नाम' अभियान प्रारम्भ किया गया है। सभी लोग अपने प्रिय लोगों के नाम एवं स्मृति में पौधा रोपित करें और उसकी देखभाल भी करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि योग एक सम्पूर्ण विधा है, जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। भारत की ऋषि परम्परा ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए योग के माध्यम से समाज व धर्म को जोड़ने का कार्य किया। भारत की ऋषि परम्परा ने धर्म के माध्यम से सांसारिक उत्कर्ष, खुशहाली, ईज ऑफ लिविंग व मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें मार्ग दिखाए हैं। योग भी हम सबको इस परम्परा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस हम सभी

भारतवासियों को अपनी विरासत का स्मरण करने और भारत की ऋषि परम्परा के प्रति श्रद्धावन्त होने का अवसर प्रदान करता है। पीएम श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों व विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 200 देश अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भारत की इस विरासत से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज स्वयं भारत के मुकुट कश्मीर में श्रीनगर स्थित डल झील पर हजारों योग साधकों के साथ सामूहिक योग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 10वें अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'स्वयं और सबके लिए योग' के साथ आज पूरे देश और दुनिया में योग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसमें जाति, क्षेत्र, भाषा, देश व काल का भेद नहीं है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम सब सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में जुड़े हैं।

## जम्मू-कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव - पीएम मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान जम्मू-कश्मीर में अपने

प्रदेशों में विभाजित जम्मू और कश्मीर में अपनी विशेष स्थिति खो दी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा

हकीकत में बदलते देख रहे हैं। इस चुनाव में आपने जम्मूरियत को जितया है। आपने पिछले 35-40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दिखाता है कि जम्मू-कश्मीर का नौजवान, जम्मूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वह समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से सरकार चुन सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह दिन भी दूर नहीं जब जम्मू-कश्मीर एक राज्य के रूप में अपना भविष्य खुद तय कर सकेगा। राज्य के दर्जे की वापसी है। इस क्षेत्र में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था और नए चुनाव की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मोदी ने कहा कि अटल जी ने जो इंसानियत, जम्मूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम



पहले संबंधन में विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा वापस करने का वादा किया। उनका यह बयान तब आया जब वह गुडवार को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में एक युवा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 2019 में दो केंद्र शासित

फिए गए वादे की प्रतीक्षा कर रहा है। इस क्षेत्र में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था और नए चुनाव की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मोदी ने कहा कि अटल जी ने जो इंसानियत, जम्मूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम

## तीन नए आपराधिक कानूनों का सीएम ममता ने विरोध किया

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर तीन आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अनुरोध किया है। बनर्जी ने इन पर संसद में आगे चर्चा की मांग की है। इसके साथ ही ममता ने आपराधिक कानूनों की नये सिरे से संसदीय समीक्षा के रूप में अपना भविष्य खुद तय कर सकेगा। राज्य के दर्जे की वापसी है। इस क्षेत्र में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था और नए चुनाव की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मोदी ने कहा कि अटल जी ने जो इंसानियत, जम्मूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम

(बीएनएसएस) 2023 के कार्यान्वयन को स्थगित करने की हमारी अपील पर विचार करें। ममता बनर्जी ने लिखा कि हमारा मानना ​​​​घट्टे कि

रखेगा। 25 दिसंबर, 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस को सहमति दी। जैसा कि अधिसूचित किया गया है,

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। सूत्रों के मुताबिक, टीएमसी प्रमुख ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से भी मुलाकात की, जो विधेयकों की जांच करने वाली संसद की स्थायी समिति का हिस्सा थे, और उनसे इस मुद्दे पर चर्चा की। टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन, द्रमुक नेता एनआर एलंगो और चिदंबरम ने तीनों विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट में असहमति जताई थी। ममता ने कहा कि ये तीनों विधेयक लोकसभा में ऐसे समय में पारित हुए, जब 146 सांसद सदन से निर्लंबित थे। ममता ने कहा, आपकी पिछली सरकार ने इन तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को एकतरफा और बिना किसी बहस के पारित कर दिया था। उस दिन, लोकसभा के लगभग 100 सदस्यों को निर्लंबित कर दिया गया था।



यह स्थगन नए सिरे से संसदीय समीक्षाध्वजादेश को सक्षम करेगा, कानूनी प्रणाली में जनता के विश्वास को मजबूत करेगा और हमारे प्यारे देश में कानून के शासन को कायम

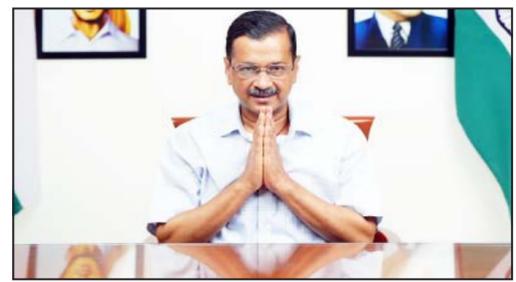
ये नए आपराधिक कानून इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होंगे हैं। नए कानून क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के

## ईडी ने हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की जमानत का किया विरोध

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़े झटके में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्हें अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंद्र डुडेजा की अवकाश पीठ ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए कहा, जब तक हाई कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं करता, तब तक रुकें। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई किए जाने तक ट्रायल कोर्ट

(राउज एवेन्यू) में कोई कार्यवाही शुरू नहीं होगी। ईडी ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि धारा

इससे बेहतर कोई कारण नहीं हो सकता। सुनवाई दोबारा शुरू होने पर प्रवर्तन निदेशालय का प्रति



45 की कठोरता पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। उसने आगे कहा कि, जमानत रद्द करने के लिए

बताते हुए इस पर सवाल उठाए। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में दलील देते हुए आरोप लगाया कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत आदेश देने से पहले सामग्री और सबूतों पर गौर नहीं किया। ईडी ने अदालत में अपनी दलील रखते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अप्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया है और जमानत देते समय प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने में विफल रही। ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एएसजी एसवी राजू ने भी कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से विकृत है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुहता केजरीवाल ने कहा, कल ही आपके सीएम को जमानत मिल गई। आदेश सुबह अपलोड किया जाना था।

## नीट पेपर लीक मामले में जो भी दोषी हो, कार्रवाई होनी चाहिए

पटना, एजेंसी। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में बयानबाजी तेज हो गई है। अब, राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूरे मामले की जांच के साथ ही जो भी दोषी मिले, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश में सरकार उनको, केंद्र में सरकार उनको, जांच एजेंसी उनको, तो फिर क्या है। अगर किसी का नाम आ रहा है, तो उसे बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री उससे पूछताछ कर लें। पेपर लीक मामले में उनके

पीएस का नाम घसीटने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को अज्ञानी बताते हुए कहा कि उन्हें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो इसके खिलाफ मई से आवाज उठा रहे हैं। इस मामले में मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाना है। इसका किंगपिन कौन है? जो भी मामला है, वह आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा। किसी का नाम घसीटने से किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्हें यह बताना चाहिए कि अमित आनंद और नीतीश कुमार कौन हैं? आखिर यही तो किंगपिन है। उनको कोई बचाने में क्यों लगा है?

## श्रीलंका के साथ भारत का मजबूत रिश्ता

नई दिल्ली, एजेंसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी एक दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका में थे। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा श्रीलंका के लिए एक विश्वसनीय मित्र और भरोसेमंद भागीदार रहेगा। हालांकि, हाल के चुनाव में कच्चातुव द्वीप जिस तरह से सुखियों में था, उसके बाद इस बात की संभावना थी कि जयशंकर के श्रीलंका दौरे के दौरान यह मुद्दा उठेगा। जयशंकर का श्रीलंका दौरा एकदिवसीय था लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका यह पांचवा दौरा है। इसी से साफ तौर पर पता चल सकता है कि भारत का रिश्ता श्रीलंका से कैसा है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री के बातचीत श्रीलंका

के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हुई है। श्रीलंका के विदेश मंत्री से भी बातचीत हुई है। कई सारे विकास

राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका का संबंध बेहद



परियोजनाओं का भी साझा रूप से उद्घाटन किया गया। विदेश मंत्री श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति से भी मिले हैं। विपक्ष के नेता से भी मिले हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई

मजबूत बना हुआ है और यह हमारे रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सहित देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की

तथा राष्ट्रपति के साथ भारत से 60 लाख अमरीकी डॉलर के अनुदान से निर्मित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। श्रीलंका पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में विक्रमसिंघे से मुलाकात की। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीं और बिजली, ऊर्जा, संपर्क, बंदरगाह बुनियादी ढांचे, विमानन, डिजिटल, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे के मार्गदर्शन में भारत-श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई।

## योग मानवता के लिए भारत का अनूठा उपहार है - राष्ट्रपति

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि योग मानवता के लिए भारत का अनूठा उपहार है और जीवनशैली से जुड़ी बढ़ती समस्याओं के कारण यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। मुर्मू ने राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकाधिक के साथ यहां राष्ट्रपति भवन में योग भी किया। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व समुदाय, खासकर भारत के नागरिकों, को बधाई।

## संपादकीय

## संख्या बढ़ाने पर विचार

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) कथित तौर पर आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती को 180 से बढ़ाकर 210 करने पर विचार कर रहा है। यह संभावित नीतिगत बदलाव एक विभागीय समिति और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) की रिपोर्ट पर आधारित है। यदि यह योजना सफल होती है, तो यह नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से उलट होगा, जिसमें सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) की भर्तियों में लगभग 40 प्रतिशत की कमी देखी गई थी। जानकार लोग विभिन्न सरकारी स्तरों पर व्यापक रिक्र्तियों के कारण अधिक बाबुओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, जो 2014 से लगभग 100 नए जिलों के जुड़ने से और बढ़ गई है। वर्तमान में, देश भर में 1,300 से अधिक आईएएस पद रिक्त हैं, जो एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। स्थिति अब सरकार को आईएएस अिाकारियों की वार्षिक भर्ती पर लगाई गई सीमा का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर सकती है। पहले, प्रचलित दृष्टिकोण यह था कि भर्ती को 180 से बढ़ाने से बाबुओं की गुणवत्ता और करियर की प्रगति से समझौता हो सकता है। अब शायद यह बदल गया है। ।कअमतजपेमउमदमदज स्प्ट रूप से, स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सूत्रों ने डीकेबी को बताया कि सरकार 51 उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव पदों को पार्श्व प्रवेश के माध्यम से भरने की योजना बना रही है ताकि रिक्र्तियों को तेजी से दूर किया जा सके। आईएस अिाकारियों की संख्या बढ़ाने का कदम हाल के वर्षों में आईपीएस अधिकारियों और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की तरह होगा। अपडेट के लिए इस स्थान पर नजर रखें। कॉरपोरेट गवर्नेंस को लागू करने के लिए एक साहसिक कदम उठाते हुए, सेबी ने पीटीसी इंडिया और इसकी सहायक कंपनी, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज (पीएफएस) के दो शीर्ष अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। पीटीसी इंडिया के सीएमडी और पीएफएस के निदेशक राजीव कुमार मिश्रा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि पीएफएस के पूर्व एमडी और सीईओ पवन सिंह पर 25 लाख रुपये का और भी अधिक जुर्माना लगाया गया ।लेकिन सेबी यहीं नहीं रुका। श्री मिश्रा और श्री सिंह दोनों को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में कोई भी बोर्ड या प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से भी रोक दिया गया है। उन्हें जनता से धन जुटाने की इच्छुक किसी भी सूचीबद्ध इकाई से जुड़ने से भी मना किया गया है। यह कार्रवाई जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद की गई है, जिसके तहत श्री सिंह को अपनी निवृत्ति तक छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। श्री मिश्रा, जो अभी भी PFS के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और च्च प्दकप के ब्दक के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, को अब इन पदों से भी हटना होगा। सेबी की कार्रवाई का उद्देश्य एक मजबूत संदेश देना है कि कॉर्पोरेट नेताओं को नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। इन दो वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदेह ठहराकर, सेबी यह बता रहा है कि शासन में चूक बढ़ाश्त नहीं की जाएगी। नियामक निवेशकों की सुरक्षा और वित्तीय बाजारों में विश्वास बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। कॉर्पोरेट भारत में पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए यह एक आवश्यक कदम है, जिससे सभी के लिए एक स्वस्थ कारोबारी माहौल का बढावा मिलता है। बाबुओं की उपलब्धियाँ सोशल मीडिया पर छा जाती हैं क्या यह सिर्फ आपके स्तंभकार की बात है, या किसी और ने भी देखा है कि कैसे कुछ बाबू अब अपनी पदोन्नति और पैनल में शामिल होने की घोषणा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं? उल्लिखितों का जश्न मनाना बहुत अच्छा है, लेकिन यह थोड़ा अप्रत्याशित लगता है। परंपरागत रूप से, आईएएस और अन्य सिविल सेवाओं में पदोन्नति और स्थानांतरण बहुत कम महत्वपूर्ण, लगभग नियमित होते थे। आप इनके बारे में समाचार पत्रों या आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सुनते होंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई अधिकारी हर दूसरे दिन टिवटर या लिंकडइन पर जश्न मनाने वाला अपडेट पोस्ट कर रहा है। जो बात वाकई दिलचस्प (या अजीब) है, वह यह है कि इन घोषणाओं का अनुसरण करने वालों और शुभचिंतकों की ओर से बाधायें की बाढ़ सी आ जाती है। ऐसा लगता है कि हर किसी के पास अवानक से अपना छोटा सा फैन क्लब है जो उन्हें उस चीज के लिए प्रोत्साहित करता है जिसे पहले एक सामान्य करियर प्रगति माना जाता था। शायद यह समय का संकेत है। सोशल मीडिया हर छोटी-छोटी जिंदगी की अपडेट को साझा करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है, तो पेशेवर मील के पत्थर भी क्यों नहीं? यह निश्चित रूप से अतीत से एक बदलाव है और शायद यह पारदर्शिता और जनता से जुड़ने के लिए भी अच्छा है। फिर भी, इतनी प्रक्रियात्मक चीज को सोशल मीडिया पर देखना थोड़ा अजीब लगता है। क्या हम आगे तबादलों के लिए हैशटैग देखना शुरू करने जा रहे हैं? जस्ट प्रमोटेड रुनेक्स्टपोस्टिंग। अंत में, अगर यह लोगों को खुश करता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो क्यों नहीं?

# दोनों ही अपने अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे कम वोटों से जीते

अजय अठारहवीं लोकसभा के लिए हाल में हुए चुनाव नतीचों का एक बड़ा निहितार्थ यह बताया जा रहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ही देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं, जो अपनी पार्टी भाजपा न सही पर चुनाव पूर्व गठबंधन एनडीए को लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज कराने में कामयाब रहे हैं। इधर खुद मोदी भी सतत तीसरी बार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पीएम पद की शपथ लेकर सरकार बनाने में सफल हुए हैं। यानी कि देश में आजादी के बाद के 75 सालों में ऐसा राजनीतिक चमत्कार दूसरी बार हुआ है, जब किसी एक राजनेता को जनता ने तीसरी बार पीएम बनने का आदेश दिया हो। यकीनन भाजपा के रूप में एक गैर कांग्रेसी सरकार की यह

बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यही एकमात्र सत्य नहीं है। कुछ अतिउत्साही और ऐतिहासिक तथ्यों से अंजान न्यूज चैनलों ने तो मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण को नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना भी बता दिया। अगर अतीत के राजनीतिक घटनाक्रमों का सांख्यिकीय विश्लेषण करें तो बात बहुत साफ हो जाएगी कि जिसे असाधारण उपलब्धि माना जा रहा है, वह वास्तव में कितनी बड़ी और अतुलनीय है।

इतिहास के गलियारों से झांकता राजनीतिक अतीत दरअसल, हम अलग-अलग मानकों पर इतिहास को जांचने की शुरुआत करें और शपथ लेने के आंकड़ों को आधार मानें तो इस मामले में पंडित जवाहरलाल सबसे आगे हैं। नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ सतत् चार बार ली। 1947 में

प्रह्लाद यूरोप में हाल ही में सम्पन्न हुए चुनावों में दक्षिणपंथी कहे जाने वाले दलों की राजनैतिक ताकत बढ़ी है। हालांकि सत्ता अभी भी वामपंथी एवं



मध्यमार्गीय नीतियों का पालन करने वाले दलों की ही बने रहने की सम्भावना है परंतु विशेष रूप से फ्रांस एवं जर्मनी में इन दलों को भारी नुकसान हुआ है। इटली की देशभ्रेम से ओतप्रोत दल की मुखिया

## वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर जल स्रोतों का निर्माण और रखरखाव जरूरी

जयसिंह वैश्विक स्तर पर वर्ष 2023 तो सबसे गर्म वर्ष माना ही गया, मगर 2024 में स्थितियां और भी विकट लग रही हैं। भारतीय मौसम विभाग की पूर्व में दी गई चेतावनी सच साबित हो रही है और चरम हीटवैव जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह स्थिति निरंतर गहराघरही है। असहनीय गर्मिं से मनुष्यों के साथ ही जीव-जंतुओं की मौतें भी बढ़ रही हैं। हिमालय से लेकर महासागर तक विभिन्न भौगोलिक ने देखा। सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के अनुसार, गर्मी से जून की शुरुआत तक देश में कम से कम 219 लोगों की मौत हो गई थी। विशेषज्ञों का

## मतिमंडल में फोकस

आदित्य मोदी के नेतृत्व में राजग—3.0 सरकार काम पर लग गई है। जाहिर है, सौ दिनों का कार्यक्रम पर काम हो रहा है। ऐसे में, उन मुद्दों को समझना जरूरी है, जो चुनाव अभियानों के दौरान छापे रहे। कृषि, पानी, उद्योग, श्रम, कौशल और रोजगार से संबंधित चिंताओं पर ६ जो राज्यों के साथ सहयोग करने विकास एवं समृद्धि के लिए प्रमुख मंत्रालयों की कार्यसूची पेश करने का अवसर प्रदान करता है। शिवराज सिंह चौहान (कृषि, कृषक कल्याण एवं ग्रामीण विकास)—कृषि क्षेत्र का संकट राजनीतिक संवादों एवं आर्थिक आंकड़ों में प्रतिध्वनित होता है। लगभग आधा यानी 45 फीसदी कार्यबल कृषि में लगा हुआ है और राष्ट्रीय आय के छठे हिस्से पर निर्भर है। यह आंकड़ा गरीबी का केंद्रीय पहलू है। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्यम होने के बावजूद उद्योग के विपरीत कृषि में आगत और निर्र्त के संबंधों का अभाव है, जो पुनः कृ षि कानूनों (जिन्हें वापस ले लिया गया था) को लाने की आवश्यकता पर बल देता है, ताकि नवाचार को अपनाया जा सके और किसान उत्पादक संगठनों एवं सहकारी समितियों के जरिये ऋण, भंडारण

जोरजीया मेलोनी को अच्छी सफलता हासिल हुई है। कुल मिलाकर यूरोपीय देशों के नागरिकों में देशभ्रेम का भाव धीमे धीमे लौट रहा है एवं वे अब अपने अपने देश में अवैध रूप

से रह रहे प्रवासियों का विरोध करने लगे हैं। विशेष रूप से यूरोप के आस पास के मुस्लिम बहुल देशों से भारी संख्या में मुस्लिम नागरिक अवैा रूप से इन देशों में शरण लिए हुए हैं एवं अब वे इन देशों की कानून

कहना है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ये गर्म लहरें अब लंबी, तीव्र और लगातार होती जाएंगी। ये विकट परिस्थितियां वन्यजीवों तथा पादप प्रजातियों के लिए भी समान रूप से घातक हैं ।धभारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है, जहां जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह स्थिति निरंतर गहराघरही है। असहनीय गर्मिं से मनुष्यों के साथ ही जीव-जंतुओं की मौतें भी बढ़ रही हैं। हिमालय से लेकर महासागर तक विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की जीव और पादप प्रजातियां रहती हैं। इनमें कुछ जीव और पादप ऐसे हैं, जो अत्यंत ठंडे या बर्फीले इलाकें में रहते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं, जो

## मतिमंडल में फोकस देतों और राजनीतिक

एवं बाजारों तक पहुंच को सक्षम बनाया जा सके। ग्रामीण विकास एवं कृषि को एक साथ लाने से लक्ष्यों में तालमेल बिठाया जा सकता है। हालांकि जरूरी सुधार पूरी तरह से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। यही बात चार बार के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता के रूप में चौहान रोजगार से संबंधित चिंताओं पर ६ जो राज्यों के साथ सहयोग करने और खेती के मुद्दों को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। चिराग पासवान (खाद्य प्रसंस्करण)—चौहान को युवा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान का भी मार्गदर्शन करना होगा। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में उच्च मुद्रास्फीति का दर्द सुना जा सकता है। आठ फीसदी से अधिक खाद्य कार्यबल कृषि में लगा हुआ है और कॉरपोरेट राजस्व पर जीडीपी के आंकड़ों में दिखाई देती है। इसका कारण असमान उत्पादन और भंडारण व प्रसंस्करण क्षमता का अभाव है। भारत को किराये पर भंडारण के लिए एक ढांचा तैयार करने की जरूरत है, जहां किसान अपनी उपज को इच्छानुसार बेचने या ऋण के लिए रिखरी रख सकें। भारत को अपनाया जा सके और किसान उत्पादक संगठनों एवं सहकारी समितियों के जरिये ऋण, भंडारण

व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। जर्मनी एवं फ्रांस ने मुस्लिम नागरिकों को मानवीय आधार पर अपने देश में बसाने में शिथिल नीतियों का पालन किया था और अब ये दोनों देश इस संदर्भ में विभिन्न समस्याओं का सबसे अधिक सामना कर रहे हैं। आज जब कई मुस्लिम देश शिया एवं सुन्नी सम्प्रदाय के नाम पर आपस में ही लड़ रहे हैं तो उनका ईसाई पंथ को मानने वाले नागरिकों के साथ सामंजस्य किस प्रकार रह सकता है, अतः यूरोपीयन देशों के नागरिकों को अब अपने किए पर परतावा होने लगा है। ब्रिटेन में भी आज मुस्लिम समाज की आबादी बहुत बढ़ गई है एवं यहां का ईसाई समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है क्योंकि मुस्लिम समाज द्वारा ईसाई समाज पर कई प्रकार के आक्रमण किया जाना आम

गर्म इलाकों में जीवित रह सकते हैं। लेकिन गर्मी और ठंड के संतुलन की जो प्राकृतिक व्यवस्था है, उसमें गड़बड़ी या असंतुलन हो जाने से जीवाभारियों के साथ ही पादपों का, जीवन भी संकट में पड़ जाता है। गर्मी बेजुबान वन्यजीवों के लिए गंभीर संकट पैदा करती है। कई जानवर, विशेष रूप से वे, जो अत्यधिक गर्मी के अनुकूल नहीं हैं, अधिक गर्मी से पीड़ित होते हैं। अत्यधिक गर्मी से निर्जलीकरण और हाइपरथर्मिया जैसी समस्याओं से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। वन्यजीव अक्सर गर्मी से बचने के लिए रात में अधिक सक्रिय हो जाते हैं जिससे उनके भोजन और सहवास का पैटर्न बाधित हो सकता है। जल स्रोत सूखने से उनके लिए पानी की कमी होती है, जिस कारण

जल स्रोतों का निर्माण और रखरखाव जरूरी

विस्तार की खातिर राज्यों में विधायी मार्ग को स्पष्ट करने की भी जरूरत है। सीआर पाटिल (जल शक्ति)—भारत में जल संकट पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया गया है और यह कई जटिल बाधयताओं से घिरा हुआ है। भंडारण, उपलब्धता, गुणवत्ता और पहुंच के मुद्दों के कारण महत्वाकांक्षी शहर घर जलश् कार्यक्रम भी आलोचनाओं के निशाने पर है। घटते जल स्तर और टैंकर आपूर्ति वाले शहरी भारत के आंकड़ों में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो 100 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में फैला है। भारत का हर प्रमुख महानगर 50 से लेकर 100 किलोमीटर से अिाक दूरी से पेपजल प्राप्त करता है। ऐसे में, एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पानी के खारेपन को दूर करने तथा रीसाइक्लिंग के लिए संयंत्र लगाना तत्काल जरूरी है। इसके लिए काफी धन की जरूरत होगी तथा पब्लिक-प्राइवेट मॉडल की आवश्यकता होगी। भारत के पास के सांवेरन और पेंशन फंड से धन जुटाने का अवसर है। एक टेक्नोक्रेट—राजनीतिक होने के नाते पाटिल के पास विरासत को संभालने का मौका है। मनसुख मंडाविया (श्रम, रोजगार एवं युवा मामले) और जयंत चौधरी (कौशल विकास)— बेरोजगारी

बात हो गई है। ब्रिटेन के कई शहरों में तो मेयर आदि जैसे उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर भी मुस्लिम समाज के नागरिक ही चुने गए हैं अतः इन नगरों में सत्ता की चाबी ही अब मुस्लिम समाज के नागरिकों के हाथों में है, जिसे ईसाई समाज के नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार, इजराईल (सूहदी समुदाय) एवं हम्मास (मुस्लिम समुदाय) के बीच युद्ध लम्बे समय से चल रहा है। ईरान (शिया समुदाय) — सऊदी अरब (सुन्नी समुदाय) के आपस में रिश्ते अच्छे नहीं है। पाकिस्तान में तो अहमदिया समुदाय एवं बोहरा समुदाय को मुस्लिम ही नहीं माना जाता है एवं इनको गैर मुस्लिम मानकर इन पर सुन्नी समुदाय द्वारा खुलकर अत्याचार किए जाते हैं। कुल मिलाकर, मुस्लिम समाज इन केवल अन्य समाज के नागरिकों (यहूदी, ईसाई, हिंदू आदि)

जानवरों को पानी की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे शिकार और मानव-वन्यजीव संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है। उच्च तापमान और वर्षा की कमी से वनस्पति भी सूख जाती है, जिससे शाकाहारी जानवरों और उन पर निर्भर मांसाहारी जानवरों के लिए भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है। जंगलों से बाहर बरितियों में भौषण गर्मी से तोते, गौरैया, नीले कबूतर, खलिहान उल्लू, काली चील, पतंगे, भारतीय भेंडिया, साप, छिपकली, नेवले, शाही, चूहा, सियार, सिवेट, बंदर और गिलहरी जैसे कई जीव प्रभावित होते हैं। गर्म तापमान परजीवी और रोगजनकों में भी वृद्धि करता है। लंबे समय तक गर्मी के तनाव से जानवरों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे वे संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील

जल स्रोतों का निर्माण और रखरखाव जरूरी

और रोजगार सृजन का मुद्दा पूरे चुनाव के दौरान गूँजता रहा। रोजगार सृजन और उपलब्ध कौशल में काफी अंतरालछ्हे। भारत को एक ऐसी श्रम नीति की जरूरत है, जो नीतियों को बाजार की जरूरतों के साथ जोड़ सके। बेशक हमारे पास कौशल विकास कार्यक्रम है, लेकिन जैसा कि संसद की स्थायी समिति ने रेखांकित किया, कुशल लोगों को प्लेसमेंट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सबसे पहले शैक्षणिक उपलब्धियों की मैपिंग, युवा कार्यबल के कौशल को प्रमाणित करने के लिए ढांचा, उद्योग की जरूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करने और कंपनियों को कर्मचारियों को कुशल बनाने एवं फिर से कौशल प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। सरकार को ग्लोबल स्किल गैप स्टडी द्वारा उजागर किए गए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। मंडाविया एवं चौधरी को अकाउंट एग्रीगेटर और ओपनडीसी पहलों में भी तेजी लानी होगी, ताकि रोजगार पैदा करने वाले स्टार्ट-अप को ऋण और बाजार तक पहुंच मिल सके। पीपूष गोयल (वाणिज्य एवं उद्योग)— बदलती भू-राजनीति, खास तौर पर अमेरिका और चीन के बीच तनाव ने वैश्विक कंपनियों को

के साथ लड़ता आया है बल्कि इस्लाम के विभिन्न फिर्कों के बीच भी इनकी आपसी लड़ाई होती रही है। इसके ठीक विपरीत, सनातन हिंदू संस्कृति का अनुपालन करते हुए कई भारतीय मूल के नागरिक भी अन्य देशों में रहे रहे हैं एवं लम्बे समय से स्थानीय स्तर पर ईसाई समाज एवं अन्य धर्मों के अनुयायियों के साथ मिल जुलकर रहते आए हैं। इन देशों में भारतीय मूल के नागरिकों एवं स्थानीय स्तर पर अन्य धर्मों के अनुयायियों के बीच कभी भी बड़े स्तर पर आक्रोश उत्पन्न होता दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि सनातन हिंदू संस्कृति में 'वखुबे कुटुम्बकम' एवं 'सर्वं भवतु सुखिनरु' का भाव हिंदू नागरिकों में बचपन से ही भरा जाता है। इसी प्रकार के भाव का संचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पिछले 99 वर्षों से अपने स्वयंसेवकों में जगाता आया है। संघ चाहता है

जल स्रोतों का निर्माण और रखरखाव जरूरी

हो जाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं, जिन पर गर्म लहरों का ज्यादा असर होता है। पक्षी विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में गर्मी के गंभीर जोखिम का सामना करते हैं। उनमें निर्जलीकरण और गर्मी से थकावट आम है। उनके घोंसले ज्यादा गरम होने से चूजे मर सकते हैं। कई सीरुप एक्टोथर्मिक होने के बावजूद, ज्यादा गरम हो सकते हैं और अगर उन्हें छाया नहीं मिलती, तो वे मर जाते हैं। हाथी और बाघ जैसे बड़े स्तनधारी भी आवास, भोजन और पानी की तलाश में मानव बरितियों के करीब आ जाते हैं, जिससे मानव-जीव संघर्ष बढ़ जाता है। विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों पर हस्तक्षेप के लिए वन्यजीव सामना करना पड़ता है। मनुष्यों की तरह ही वन्यजीवों के संरक्षण को

## मजबूरियों की झलक

जस्ट-इन-टाइम (जरूरत पड़ने पर ही आपूर्तिकर्ताओं से सामान मंगाना) से जस्ट- इन- केस (किसी उत्पाद के स्टॉक से ज्यादा बिकने की संभावना



को कम करना) बिजनेस मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित किया है। भारत वैश्विक विनिर्माण में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के वैश्विक अक्सर के चौराहे पर खड़ा है। मई में पीडब्ल्यूसी द्वारा प्रकाशित एक संक्षेप के मुताबिक, भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अमेरिका और चीन के बाद, तीसरी सबसे अहम कड़ी के रूप में उभर रहा है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में। हां, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना कुछ क्षेत्रों में फायदा पहुंचा रही है, लेकिन और काम करने की जरूरत है। सुधारों के अक्षरें एजेंडे का बोझ राज्यो पर है और यहां नीति आयोग

कि संसार में सदगुणों का बोलबाला हो। 27 सितम्बर 1933 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, शरत्र पूजा समारोह में अपने उदबोधन में कहते हैं कि ष्पंध एक हिंदू संगठन है। संसार के सभी धर्मों में हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है, जिसका मुख्य गुण सदगुण है और जो श्आत्मवत् भूतेषु (सभी प्राणियों में अपने को देखना) की भावना से सभी जीवों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना सिखाता है। यह धर्म संसार में व्याप्त हिंसा और अन्याय को स्वीकार नहीं करता। इसलिए स्वाभाविक है कि प्रत्येक हिंदू ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहता है। लेकिन केवल उपदेश देने से संसार का स्वभाव नहीं बदलेगा। जब संसार को लगेगा कि हिंदू समाज सुसंगठित और सशक्त हो गया है।

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी का

उपयोग होना चाहिए। जरूरी है कि वन्यजीवों पर गर्मी के दीर्घकालिक प्रभावों को समझने और शानन रणनीतियों को विकसित करने के लिए विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण किया जाए। स्थानीय समुदायों को चरम मौसमी घटनाओं के दौरान वन्यजीवों की मौतों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि एक व्यापक डाटाबेस बनाया जा सके। वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर जल स्रोतों का निर्माण और रखरखाव जरूरी है। वन्यजीवों के पर्यावास के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। अत्यधिक गर्मी के दौरान समय पर हस्तक्षेप के लिए वन्यजीव स्वास्थ्य और व्यवहार की निरंतर निगरानी होनी चाहिए।

जल स्रोतों का निर्माण और रखरखाव जरूरी

सर्वोत्तम प्रथाओं की एक ब्लू बुक बनाकर बदलाव ला सकता है। भारत को नई श्रम संहिताओं को अपनाने में तेजी लानी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के



उपक्रमों की अधिशेष भूमि का लाभ उठाकर निवेश करने वाली कंपनियों के लिए जगह बनानी होगी और नियामकीय बाधाओं को दूर करना होगा। भारत को निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए और अधिक औद्योगिक समूहों की आवश्यकता है, विशेष रूप से पूर्वी तट और उत्तर के संसाह्रान संपन्न राज्यों में। मंत्रिमंडल के मंत्रियों के चयन से व्यक्तित्व के साथ फोकस क्षेत्रों के दिलचस्प जुड़ाव, राजनीतिक मजबूरियों और आर्थिक अनिवार्यताओं का पता चलता है। यह देखना अभी बाकी है कि इस पूरे बदलाव से वादे के मुताबिक नतीजे मिलते हैं या नहीं।



